भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] No. 177] दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2016/भाद्र 1, 1938

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 163

DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2016/BHADRA 1, 1938

[N.C.T.D. No. 163

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विघान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली. 22 अगस्त. 2016

विधेयक संख्या (04) 2016

दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) विधेयकए 2016

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 में पुनः संशोधन के लिए एक विधेयक

सं. 21(27)/विलासिता (ए)/2016/वि. स. स.—VI/वि./6649.—इसे भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाएगा:—

- तघु शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभ:-(1) यह अधिनियम दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा।
 (2) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से लागू होगा :
- 2. **धारा 2 का संशोधन** :— दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996, खण्ड (1) के उपखण्ड (3) में "टेलिविजन तथा उस जैसे" शब्दों के पश्चात् आये शब्दों "सात सौ पचास" के लिए तथा "रूपये प्रति कमरा प्रतिदिन या अधिक" शब्दों से पहले "एक हजार पांच सौ" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 3. **धारा ८ का संशोधन** :– दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 की धारा ८ की उप धारा (1) में तालिका में क्रम सं. 3 पर "होटल आवास प्रभार सिहत" शब्दों के पश्चात् आये "750/—रू" के लिए तथा "प्रतिदिन प्रति कमरा या अधिक" शब्दों से पहले "1,500/— रू" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4112 DG/2016 (1)

उद्देश्य एवं कारणों का विवरण

- 1 इस समय विलासिता कर के लिए प्रारंभिक सीमा 750 / —रू. प्रतिदिन प्रति कमरा का प्रावधान है। कर प्रणाली को सरल बनाने बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए इस प्रारंभिक सीमा को 750 / —रू. से बढ़ाकर 1500 / —रू. प्रतिदिन प्रति कमरा किया जा रहा है। इससे नागरिकों तथा पर्यटकों पर बोझ कम होगा और छोटे होटलो को अपना व्यापार करने में आसानी होगी।
- 2 इन प्रस्तावों से व्यापार सरल होगा और विलासिता कर विभाग की कार्य प्रणाली में प्रक्रिया संबंधी भारी बदलाव आएगा। विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ज्ञापन

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2016 में किसी अधिकारी को अधीनस्थ विधान बनाने की शक्तियों के प्रत्यायोजन के विषय में कोई प्रावधान नहीं है।

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2016 में किसी प्रकार की वित्तीय विवक्षा सम्मिलित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से नये पदों पर कोई खर्च अपेक्षित नहीं है।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NOTIFICATION

Delhi, the 22nd August, 2016

BILL NO 04 OF 2016.

THE DELHI TAX ON LUXURIES (AMENDMENT) BILL, 2016

A Bill further to amend Delhi Tax on Luxuries Act, 1996

No. 21 (27)/Luxuries (A)/2016/LAS-VI/Leg./6649.—Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the Sixty Seventh year of the Republic of India as follows:-

- 1. **Short title, extent and commencement:-** (1) This Act may be called the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act, 2016.
 - (2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- 2. **Amendment of Section 2:-** In the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996, in clause (*i*), in sub-clause (iii) for the words "seven hundred fifty" occurring after the words "television and the like, is" and before the words "rupees per room per day or more", the words "one thousand five hundred" shall be substituted.
- 3. **Amendment of Section 8:-** In the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996, in section 8, in sub-section (1) at Serial No. 3 in the table for "Rs 750/-" occurring after the words "Hotel accommodation with tariff" and before the words "per day per room or more", "Rs 1,500/-" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

- 1. As per the present provisions the threshold limit for Luxury Tax is Rs 750/- per day per room. As another step towards a simplified tax regime, it has been decided to increase the threshold limit from Rs 750/- to Rs 1,500/- per day per room. This will reduce burden on citizens and tourists and make it easy for small hotels to do business.
- 2. The proposal will ease business and will be a major process change in the functioning of the Luxury Tax Department.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Amendment) Bill, 2016 does not involve any additional financial implications since no outgo on new posts is anticipated from the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Amendment) Bill, 2016 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation.

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA, Secy.